



















आम बजट

2017-18

हाईलाइट्स



~दवारा संकलित~

Admin: <u>UPSC Hindi Medium</u> Channel





























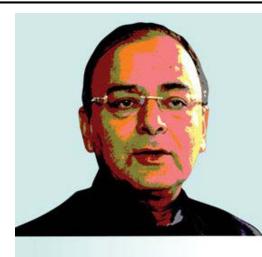












बजट में कसे क्या मला?



 बेघरों के लिए **1 करो**ड मकान, बुजुर्गों के लिए आधार बेस्ड हेल्थ कार्ड।



→ IRCTC से टिकट बुक कराने वालों को नहीं देना होगा सर्विस चार्ज।



🔷 ३.५ करोड़ यूथ्स को ट्रेनिंग, बड़ी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी।



 किसानों को १० लाख करोड का कर्ज।

अरुण जेटली ने बुधवार को बजट पेश किया। इसे किसान, रूरल डेवलपमेंट, यूथ्स, गरीबों के लिए मकान और डिजिटल इकोनॉमी जैसे 10 हिस्सों में बांटा गया है। सरकार ने 3 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। वहीं, तीन नए रिफॉर्म प्रपोज किए हैं। पहला- पॉलिटिकल पार्टियां 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा कैश में नहीं ले सकेंगी। दूसरा- देश से भागने वाले अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करने के लिए सख्त कानून लाया जाएगा। तीसरा- 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजेक्शन पर अप्रैल से रोक लगाई जाएगी। बजट के 10 हाईलाइट्स







































- 1.2019 तक 1 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
- 2.अब पोस्ट ऑफिस से भी बन सकेंगे पासपोर्ट।
- 3. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनेगी जो हायर एजुकेशन के लिए सभी बड़ी एंट्रेंस एग्जाम्स कराएगी। इससे सीबीएसई जैसी संस्थाएं एकेडिमक्स पर फोकस कर पाएंगी।
- 4.झारखंड और गुजरात में दो नए एम्स बनाए जाएंगे।
- 5.IRCTC से टिकट बुक कराने पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा।
- 6.3.5 करोड़ यूथ्स को मार्केट बेस्ड ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए संकल्प स्कीम्स का एलान किया। इस काम के लिए सरकार ने 4000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं।
- 7.व्मन और चाइल्ड वेलफेयर के लिए 1.84 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन।
- 8. किसानों का 60 दिन का ब्याज माफ होगा। 40 फीसदी किसानों को कोऑपरेटिव सोसायटीज से क्रेडिट मिलेगा। फसल बीमा योजना में कवरेज को 40% बढ़ाया गया है।
- 9. एक लाख 50 हजार ग्राम पंचायतों को हाईस्पीड ब्रॉड बैंड सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 10 हजार करोड़ रुपए अलॉट किए गए।
- 10. सीनियर सिटिजन के लिए आधार बेस्ड स्मार्ट कार्ड बनेंगे जो उनकी सेहत का रिकॉर्ड रखेंगे।







































बजट को 10 हिस्सों में बांटा

- -किसानों की इनकम पांच साल में दोगुना करने का लक्ष्य।
- रूरल डेवलपमेंट में इन्फ्रास्ट्रक्चर।
- -यूथ्स को जॉब्स।



- -गरीबों के लिए मकान।
- -सोशल सिक्युरिटी बढ़ाना।
- -क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर।
- -डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना।
- -पब्लिक सर्विस में लोगों की भागीदारी बढ़ाना।
- -ऐसा मैनेजमेंट जिससे रिसोर्सेस मोबाइल हो।
- -ईमानदार का सम्मान हो।











































किस सेक्टर को क्या मिला?

एग्रीकल्चर

- -किसानों को 10 लाख करोड़ का कर्ज मिलेगा। वहीं, 60 दिन का ब्याज माफ किया जाएगा।
- 40 फीसदी किसानों को कोऑपरेटिव सोसायटीज से क्रेडिट मिलेगा। फसल बीमा योजना में कवरेज को 40% बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 9 हजार करोड़ रुपए।
- सॉयल हेल्थ कार्ड के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों में मिनी लैब्स बनाने का प्रावधान किया गया है ताकि किसान वहां जाकर अपनी खेती की जमीन की मिट्टी का टेस्ट कर सकें।
- पर ड्रॉप-मोर क्रॉप को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उम्मीद है कि अच्छे मानसून के चलते एग्रीकल्चर सेक्टर इस साल 4.1% की दर से बढ़ेगा।
- अगले 5 साल में किसानों की इनकम डबल किए जाने का एलान। माइक्रो इरिगेशन और डेयरी प्रोसेसिंग के 13,000
- किसानों को शॉर्ट-टर्म फसलों के लिए 3 लाख तक का लोन 7% के इंट्रेस्ट रेट से दिया जाएगा। सही समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को केवल 4% इंट्रेस्ट देना होगा।

रूरल



- 2017-18 में मनरेगा के लिए 48 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस स्कीम के लिए यह अब तक का सबसे बडा बजट अलॉकेशन है।
- मनरेगा के तहत 2017-18 में 5 लाख तालाब और बनाए जाएंगे। महिलाओं की मनरेगा में 55% भागीदारी
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2016-17 में हर दिन 133 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। इसे बढ़ाया जाएगा।

- 5 स्पेशल दूरिज्म सेक्टर बनाए जाएंगे।
- इन्क्रेडिबल इंडिया का सेकंड कैम्पेन लॉन्च होगा।





Jobs



SSC







PCS





eBooks























<u>एजुकेशन</u>

- -नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनेगी जो हायर एजुकेशन के लिए सभी बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स कराएगी। इससे सीबीएसई जैसी संस्थाएं एकेडमिक्स पर फोकस कर पाएंगी।
- सरकार SWAYAM प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी। इसमें करीब 350 कोर्स होंगे। स्टूडेंट्स इन्हें ऑनलाइन एक्सेस कर सकेंगे। इसे डीटीएच चैनल्स से भी लिंक किया जाएगा।
- यूजीसी के जरिए अच्छी क्वालिटी के इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे।
- 3.5 करोड़ यूथ्स को मार्केट बेस्ड ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए संकल्प स्कीम्स का एलान किया। इस काम के लिए सरकार ने 4000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं।
- पीएम स्किल सेंटर को 600 जिलों में शुरू किया जाएगा।



- -झारखंड और गुजरात में 2 नए एम्स बनाए जाएंगे।
- गरीबी को खराब हेल्थ से जोड़कर देखा जाता है। सरकार ने एक्शन प्लान बनाया है। कई बड़ी बीमारियों को हटाने का प्लान बनाया गया है।
- सीनियर सिटीजन के लिए आधार बेस्ड स्मार्ट कार्ड बनेंगे, जो उनकी सेहत का रिकॉर्ड रखेंगे।
- डॉक्टरों की कमी के मद्देनजर मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेज्एशन की 5000 सीटें बढ़ाई जाएंगी।

- 1 लाख 50 हजार ग्राम पंचायतों को हाईस्पीड ब्रॉड बैंड सर्विस प्रोवाइड की जाएगी।
- भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 10 हजार करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं।

इन्फ्रास्टक्चर

- नए जॉब्स और बजट में किफायती घरों के लोए 3,96,135 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं।
- 64900 करोड़ रुपए हाई-वे के लिए अलॉट किए गए। 2014 से 2016-17 तक 1,40,000 किलोमीटर सड़क बनी।
- ट्रांसपोर्ट के लिए 2,41,387 करोड़ रु. का बजट का प्रोविजन किया गया।
- अफोर्डेबल हाउसिंग को इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में शामिल किया गया है।

















eBooks





































रेलवे

- -IRCTC से टिकट बुक कराने पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा।
- रेल सेफ्टी फंड के तहत पांच साल के लिए 1 लाख करोड़ मिलेंगे। 2020 तक ब्रॉडगेज लाइन पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म कर दी जाएगी।
- -25 स्टेशनों का रि-डेवलपमेंट होगा। 500 स्टेशन डिफरेंटली एबल्ड फ्रैंडली बनाए जाएंगे। 7000 स्टेशंस को सोलर पावर से चलाया जाएगा।
- नई मेट्रो रेल पॉलिसी का एलान होगा। नया एक्ट बनेगा। इससे प्राइवेट पार्टिसिपेशन में मदद मिलेगी।



- सरकार ने डिफेंस बजट में 6.2% की बढ़ोतरी की है।
- नए 2017-18 के लिए 2.74 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। साल 2016-17 में यह 2.58 लाख करोड़ रुपये था।

स्पोर्टस

- स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के बजट में 350 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है।
- इस साल 1493 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। पिछले साल यह रकम 1592 करोड़ रुपए थी।

स्टार्ट-अप

- स्टार्ट-अप सेक्टर को बजट में बड़ी राहत दी गई है।
- स्टार्ट-अप पर तीन साल के लिए टैक्स छूट समय सीमा को बढ़ाकर सात साल करने का एलान किया गया।





Jobs



SSC





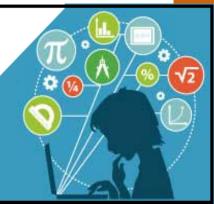






eBooks























आम बजट में इनकम टैक्स



टैक्स रेट	नया टैक्स रेट
0%	कोई बदलाव नहीं
10%	5% e
20%	कोई बदलाव नहीं
30%	कोई बदलाव नहीं
	0% 10% 20%

अरुण जेटली ने आम बजट में इनकम टैक्स को घटाने का एलान किया है। अब आपकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए है तो टैक्स नहीं देना होगा। पहले ढाई से पांच लाख रुपए की इनकम पर पहले 10% टैक्स लगता था। अब यह आधा यानी 5% ही लगेगा। 5 से 10 लाख रुपए के स्लैब में टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन्वेस्टमेंट दिखाने के बाद 5 लाख रुपए तक की इनकम वालों को सालाना 12500 रुपए का फायदा मिल सकता है। पहले

क्या थी स्लैब और अब क्या आया बदलाव...









































पहले ये थी टैक्स स्लैब

- 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता था।
- 2.5 से 5 लाख रुपए की इनकम पर 10% टैक्स लगता था।
- 5 से 10 लाख रुपए की इनकम पर 20% टैक्स लगता था।
- 10 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स लगता था। सभी स्लैब में इनकम टैक्स पर 3% एजुकेशन सेस भी लगता था।

बदलाव को इस तरह समझें



- 3 से 3.5 लाख रुपए की इनकम पर 2500 रुपए टैक्स लगेगा।
- 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% टैक्स।
- 5 से 10 लाख रुपए तक 20% टैक्स और 10 लाख रुपए से ज्यादा इनकम पर 30% टैक्स को बरकरार रखा गया है।

3 लाख रुपए तक की इनकम इस तरह होगी टैक्स फ्री

- ढाई लाख रुपए तक की इनकम पर फिलहाल कोई टैक्स नहीं लगता।
- ढाई लाख से तीन लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा।
- यानी 50 हजार रुपए की इस टैक्सेबल इनकम पर 5 फीसदी टैक्स हुआ 2500 रुपए।
- सरकार ने 3.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर 2500 रुपए टैक्स में छूट दे रखी है।
- इस तरह अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए है तो आपको जीरो टैक्स देना होगा।

5 लाख रुपए तक की इनकम पर भी नहीं देना होगा टैक्स

- फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने कहा है कि अगर मौजूदा इन्वेस्टमेंट लिमिट का इस्तेमाल किया जाए तो सालाना 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। सीए अतुल गर्ग ने बताया कि 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। बाकी 1.5 लाख रुपए आप 80C के तहत इन्वेस्ट कर टैक्स छूट पा सकते हैं। इसके अलावा होम लोन ब्याज पर भी टैक्स छूट पा सकते हैं। इस तरह से आप को 5 लाख रुपए की सालाना इनकम पर भी टैक्स नहीं देना होगा।





Jobs



































5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम वालों के लिए आएगा 1 पेज का ITR फॉर्म

सरकार ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए 5 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम वाले इंडीविजुअल टैक्सपेयर के लिए 1 पेज का ITR फॉर्म लाने की घोषणा की है। इससे इस कैटेगरी के लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आसान होगा।

अमीरों के लिए कितना टैक्स?



- जेटली ने कहा कि 50 लाख से 1 करोड़ रुपए की सालाना इनकम रखने वालों को 30% टैक्स पर 10% सरचार्ज देना होगा।
- वहीं, 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स पर 15% सरचार्ज लगेगा।

नोटबंदी के दौरान बड़ी रकम जमा हुई, फिर भी टैक्स नहीं देती हमारी सोसायटी

- जेटली ने बजट स्पीच में कहा कि भारत बड़े पैमाने पर टैक्स नहीं देने वाली सोसायटी है। जो लोग टैक्स नहीं देते, वे ईमानदारी से टैक्स भरने वालों का अपमान करते हैं।
- उन्होंने कहा कि पिछले साल नोटबंदी के बाद 1.09 करोड़ बैंक खातों में 2 लाख से 80 लाख रुपए तक का डिपॉजिट हुआ। एवरेज डिपॉजिट 5 लाख रुपए था। 1.48 करोड़ बैंक खाते ऐसे सामने आए जिनमें 80 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा हुई। हर खाते में एवरेज 3.31 करोड़ रुपए नोटबंदी के दौरान जमा हुए।
- जेटली ने बताया कि देशभर में 76 लाख लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने अपनी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा बताई है। इनमें से भी 56 लाख लोग सैलरी क्लास के हैं।

10 साल पुराने केस भी ओपन कर सकेंगे IT अफसर

- इनकम टैक्स अफसर अब अघोषित आय और 50 लाख से ज्यादा संपत्ति के 10 साल पुराने मामले भी ओपन कर सकेंगे।
- ऐसे मामलों में अभी तक IT अफसर 6 साल पुराने मामलों की जांच कर सकते हैं। लेकिन, इनकमटैक्स एक्ट में अमेंडमेंट से ये सीमा 4 साल और बढ़ जाएगी। अमेंडमेंट 1 अप्रैल 2017 से लागू होगा।
- अमेंडमेंट के पीछे सरकार का मकसद ब्लैकमनी पर लगाम लगाना है।





Jobs







Bank









eBooks























इन फोटोज के द्वारा बजट को समझिए:



- 10 लाख करोड़ का कर्ज मिलेगा। 60 दिन का ब्याज माफ किया जाएगा।
- अगले 5 साल में किसानों की इनकम डबल किए जाने का एलान।
- किसानों को शॉर्ट-टर्म फसलों के लिए 3 लाख तक का लोन 7% के इंट्रेस्ट रेट पर मिलेगा।





- झारखंड और गुजरात में 2 नए एम्स बनाए जाएंगे।
- सीनियर सिटीजन के लिए आधार बेस्ड हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे।
- गर्भवती महिलाओं के अकाउंट में 6 हजार रु. ट्रांसफर होंगे।
- मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएशन की 5000 सीटें बढ़ाई जाएंगी।









































- ▶ IRCTC से टिकट बुक कराने पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा।
- 🎐 २५ स्टेशनों का रि-डेवलपमेंट होगा।
- 🏓 ५०० स्टेशन दिव्यांग फ्रैंडली बनाए जाएंगे।
- 🌶 ७००० स्टेशंस को सोलर पावर से चलाया जाएगा।





- नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनेगी जो हायर एजुकेशन के लिए सभी बड़े एंट्रेंस कराएगी।
- ♦ SWAYAM प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा। इसमें करीब 350 ऑनलाइन कोर्स होंगे।
- 🌶 ३.५ करोड़ यूथ्स को मार्केट बेरड ट्रेनिंग दी जाएगी।
- 600 नए जिलों में शुरू होंगे पीएम स्किल सेंटर।



































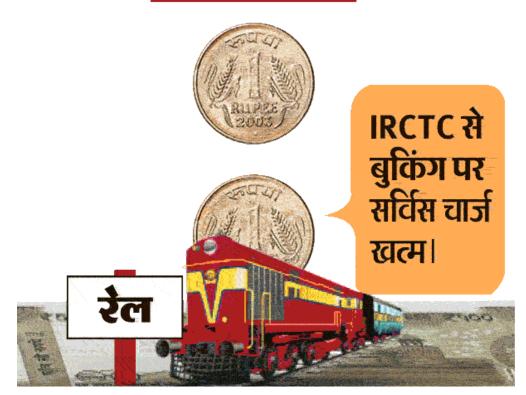








बजट 2017-18



ਕजट 2017-18











SSC



















lobs



















छोटी कंपनियों का कॉरपोरेट टैक्स 30 से 25% किया गया।

🍑 ५० करोड़ से से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों को टैक्स में ५% की राहत।



















